बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 194 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 19 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों, सेवादारों और अन्य कर्मचारियों के वेतन व सुविधाओं की समीक्षा के लिए न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि यदि कोई पक्ष वास्तव में प्रभावित है तो वह सीधे अदालत का रुख कर सकता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि उन्हें पुजारियों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए.

बैंक धोखाधड़ी केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दीपक सिंगला को किया गिरफ्तार, आप ने बीजेपी पर बोला हमला

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के आवास पर छापा मारा। सोमवार को दिल्ली और गोवा समेत कई ठिकानों पर ईडी की टीमों ने एक साथ छापेमारी की। आप नेता दीपक सिंगला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

सिंगला की गिरफ्तार पर केजरीवाल का बड़ा दावा

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उसने कोई गलत काम किया है। बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ काम कर रहा था और उसने भाजपा में शामिल होने से मना कर दिया। दीपक बहादुर है और देश के लिए लड़ रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपने पर्सनल गुंडों की तरह इस्तेमाल करके मोदी जी विपक्ष के नेताओं को चुनाव जीतने से रोक सकते हैं। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को, रुपए की गिरती इज्जत को नहीं संभाल सकते। ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को अपने पर्सनल गुंडों की तरह इस्तेमाल करके मोदी जी विपक्ष के नेताओं को चुनाव जीतने से रोक सकते है ..

ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर बरसीं आतिशी

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, आज हमारे देश में नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोल-डीजल-सीएनजी के दाम रोज बढ़ रहे हैं, रुपया डॉलर के सामने गिरता जा रहा। लेकिन मोदी जी को सिर्फ एक काम है-विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना। आज ईडी ने आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है। क्योंकि वो गोवा में भाजपा के खिलफ लड़ने वाला एक संगठन तैयार कर रहे थे। मोदी जी आप चाहे हमारी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार करो, हम देश के हित के लिए काम करते रहेंगे।

राहुल गांधी की जिन्ना से तुलना पर सियासी बवाल, कांग्रेस बोली- बीजेपी ध्यान भटका रही है

नई दिल्ली । कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से करने की कड़ी आलोचना की और इस टिप्पणी को राजनीतिक अदूरदर्शिता और इतिहास की अज्ञानता का प्रदर्शन बताया। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से करने वाली टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि जिन्ना ने देश को विभाजन की त्रासदी में धकेल दिया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत था। पार्टी ने कहा कि इस देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए रक्त, पसीना और प्राणों का बलिदान देने की विरासत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के लिए जेल जाकर अपनी जान कुर्बान की है। और आगे कहा कि उसी कांग्रेस के नेताओं की तुलना जिन्ना से करके भाजपा नेताओं ने अपनी राजनीतिक दिवालियापन को उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने जोशी की अपनी ही पार्टी के इतिहास की समझ पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या जोशी अविभाजित बंगाल में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग द्वारा चलाई गई गठबंधन सरकार को भूल गए हैं? क्या उन्हें एल.के. आडवाणी का वह बयान याद नहीं है जिसमें उन्होंने जिन्ना को 'धर्मनिरपेक्ष नेता' बताया था? इतिहास गवाह है कि भाजपा के कई नेताओं ने जिन्ना के प्रति नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस ने भाजपा पर इतिहास का चुनिंदा इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लिए सचाई असहनीय है। जो नेता कांग्रेस पर हमला करने के लिए देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटते हैं, उन्हें पहले अपनी विचारधारा की जड़ों का इतिहास पढ़ना चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अप्रासंगिक और भड़काऊ मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस ने आगे कहा कि राहुल गांधी ऐसी राजनीति करते हैं जो देश की जनता को एकजुट करती है। लेकिन भाजपा जाति, धर्म और नफरत के आधार पर समाज को बांटने वाली फैक्ट्री बन गई है, खासकर चुनावों से पहले। इसमें आगे कहा गया कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर यह बहुत कठिन लगे, तो उन्हें कम से कम भाजपा की राजनीतिक उत्पत्ति का अध्ययन करना चाहिए। तभी कांग्रेस और भाजपा के बीच दार्शनिक और त्यागपूर्ण अंतर स्पष्ट होगा।

जमानत नियम है, जेल अपवाद, उमर खालिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; पुराने फैसले पर जताई आपत्ति

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से जुड़े अपने पुराने फैसले के कुछ पहलुओं पर गंभीर टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे सख्त कानूनों के मामलों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद होना चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करी और आतंक फंडिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी को जमानत देते समय की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनवरी में शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते समय तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ के एक महत्वपूर्ण फैसले का सही तरीके से पालन नहीं किया था। तीन-न्यायाधीशों की उस पीठ ने माना था कि यदि किसी मामले में ट्रायल में अत्यधिक देरी हो रही है, तो यह जमानत देने का एक वैध आधार हो सकता है, भले ही मामला यूएपीए के तहत दर्ज हो।

त्वरित सुनवाई का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी आरोपी का त्वरित सुनवाई का संवैधानिक अधिकार केवल इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर यूएपीए जैसा सख्त कानून लगाया गया है। पीठ ने कहा कि लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने की स्थिति में अदालतों को आरोपी के मौलिक अधिकारों पर भी ध्यान देना चाहिए।

दिल्ली दंगा साजिश केस फिर चर्चा में

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस लगातार जारी है। इस मामले में कई छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे। उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों लंबे समय से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिकाएं पहले भी अदालतों में चर्चा का विषय रही हैं।

दिल्ली में शुरू हुआ जनगणना अभियान, घर-घर पहुंचकर जुटाई जाएगी ये जरूरी जानकारी

देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनगणना अभियान का पहला चरण शनिवार से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है. अगले 30 दिनों तक चलने वाले इस बड़े सर्वे अभियान के तहत 14 जून तक राजधानी के हर इलाके में घरों की गिनती और मकानों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. प्रशासन इसे आने वाले वर्षों की सरकारी नीतियों और योजनाओं की बुनियाद मान रहा है. दिल्ली में इस विशाल प्रशासनिक प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने के लिए करीब 50 हजार सरकारी कर्मचारियों और प्रगणकों को मैदान में उतारा गया है. इन सभी को पहले विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि सर्वे के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. जनगणना टीम दिल्ली नगर निगम के अलग-अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में जाकर लगभग 32 लाख मकानों का डेटा जुटाएगी. कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों से जानकारी लेंगे और उसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे. इस सर्वे के दौरान नागरिकों से कुल 33 अहम सवाल पूछे जाएंगे. इनमें मकान, परिवार, सुविधाएं और संपत्ति से जुड़ी जानकारियां शामिल होंगी. अधिकारियों का कहना है कि लोगों द्वारा दी गई हर जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. प्रशासन ने साफ किया है कि जनगणना प्रक्रिया में शामिल होना सभी नागरिकों के लिए जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति सर्वे में सहयोग करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. लोगों की सुरक्षा और भरोसे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सत्यापन की सुविधा भी दी है. नागरिक जनगणना कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों का पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र जांच सकते हैं. इसके अलावा पहचान पत्र पर मौजूद क्यूआरकोड स्कैन कर उनकी प्रामाणिकता भी पता की जा सकती है. जनगणना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लगातार मना करने पर सेंसस एक्ट 1948 की धारा 11 के तहत 1000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

अवैध स्विमिंग पूल बने मौत का कुआं - 100 से 300 रुपये प्रति घंटा शुल्क, सुरक्षा जीरो; मासूम की मौत ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। वजीराबाद के जगतपुर गांव में अवैध रूप से संचालित स्विमिंग पूलों की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां 100 से 300 रुपये प्रति घंटा शुल्क लेकर कई स्विमिंग पूल चलाए जा रहे हैं। पर, इनमें न प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर हैं, न लाइफगार्ड है, न लाइफ जैकेट और न ही पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम हैं। 10 वर्षीय संस्कार वर्मा की मौत के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संस्कार के पिता नीरज वर्मा का कहना है कि यदि पूल पर सुरक्षा गार्ड या प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद होते तो शायद उनका बेटा आज जीवित होता। उन्होंने सवाल उठाया कि उनका बेटा गहरे पानी में कब पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को क्यों नहीं हुई? हादसे की सूचना मिलने के बाद जब संस्कार के परिजन और स्थानीय लोग मिलन विहार स्थित पूल पहुंचे, तो कथित तौर पर वहां मौजूद प्रभावशाली लोगों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया।

परिवार ने कहा-जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो

संस्कार के पिता नीरज वर्मा ने बताया कि वह दोस्तों के बच्चों के साथ स्विमिंग के लिए गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सुरक्षा मानकों के अवैध तरीके से स्विमिंग पूल संचालित किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है। परिवार ने निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पूल के लिए बोरवेल लगाए गए...प्रशासन ने नहीं की फिक्र

स्थानीय निवासी भी बताते हैं कि पूल संचालकों का क्षेत्र में दबदबा है। उनका भी कहना है कि हादसे के बाद उन्होंने लोगों को पूल के आसपास जाने से भी रोका। स्थानीय लोगों के अनुसार, इलाके में तीन से चार स्विमिंग पूल अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। इन पूलों के लिए बड़े पैमाने पर बोरवेल लगाए गए हैं फिर भी प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। संस्कार की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

पिता नीरज ने बताया कि शनिवार रात काफी आग्रह के बाद उनके दोस्त महेंद्र बच्चों को स्विमिंग के लिए साथ ले जाने को तैयार हुए थे। पहले बच्चों का जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दोनों बेटों के लिए 500 रुपये शुल्क भी जमा कराया गया था। अब नीरज उसी फैसले को याद कर खुद को कोस रहे हैं। दिल्ली के वजीराबाद स्थित जगतपुर गांव के मिलन विहार में रविवार सुबह अवैध रूप से चलाए जा रहे स्विमिंग पूल में डूबकर 10 साल के मासूम की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त संस्कार वर्मा (10) के रूप में हुई है। रविवार को सुबह संस्कार छात्रा के एक समूह के साथ निजी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आया था। इस बीच वह गलती से गहरे पूल में गया और डूब गया। कुछ ही देर बाद बड़े लड़के जब पूल में नहाने के लिए उतरे तो उन्होंने पूल के तली में संस्कार को डूबे हुए देखा। शोर मचाने पर फौरन उसे पूल से निकालकर नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सिविल लाइंस स्थित ट्रामा सेंटर भेजा गया, वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

सुदृढ़ आयाम

उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वावलंबन और स्थानीय सुशासन की एक ऐसी आधारशिला बनकर उभरी है जिसने गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को न केवल आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर किया है। जनपद लखनऊ के धरातल पर हुए बदलावों का आकलन करें तो बीते नौ वर्षों की समय-अवधि ग्रामीण उत्थान के पन्नों में एक नए युगांतरकारी दौर के रूप में दर्ज हुई है जहां विकास की प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। आधारभूत संरचना, स्वच्छता, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में हुए इन अभूतपूर्व कार्यों ने प्रगति की एक नई परिभाषा गढ़ी है। विकास की इस अविरल धारा ने गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है जिससे ग्रामीण परिवेश में एक सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आज पूरी तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ और जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निर्मित पंचायत भवनों ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। ये भवन अब केवल सरकारी इमारतें मात्र नहीं रह गए हैं बल्कि ग्रामीण सचिवालयों के रूप में विकसित होकर स्थानीय सुशासन का जीवंत केंद्र बन चुके हैं। यहाँ आयोजित होने वाली ग्राम सभाएं, विकास योजनाओं की नियमित बैठकें और महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियां स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बन रही हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सचिवालय ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे ग्रामीणों को अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए अब शहरों की ओर नहीं दौड़ना पड़ता। आधुनिक कार्यप्रणाली से युक्त इन सचिवालयों ने ग्राम स्तर पर सुशासन की संकल्पना को पूरी तरह धरातल पर उतारा है। इसी कड़ी में ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के माध्यम से पंचायतों का संपूर्ण डिजिटलीकरण किया गया है जिसने प्रशासनिक दक्षता को एक नए स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में जनपद ने जो मील के पत्थर स्थापित किए हैं वे पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायी हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन से व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई है उसने न केवल महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित किया है बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य सूचकांकों में भी व्यापक सुधार किया है। इसके साथ ही सैकड़ों सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है जो विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं। खुले में शौच से मुक्ति ने लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारियों में उल्लेखनीय कमी लाई है। ओ.डी.एफ प्लस की अवधारणा को साकार करते हुए अब गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण पर्यावरण पूरी तरह स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बना रहे। जनपद के सर्वांगीण विकास में ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर वातावरण निर्माण और पारिस्थितिकीय विश्लेषण कर स्वयं ग्रामीणों द्वारा अपनी तात्कालिक प्राथमिकताओं का चयन किया जाता है। इसी जनभागीदारी के आधार पर गांवों में सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, पेयजल और सोलर लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा रहा है। खेल मैदानों के विकास ने जहाँ ग्रामीण युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए नई ऊर्जा दी है वहीं सौर ऊर्जा योजनाओं के समावेश से घरों को मुफ्त बिजली की सुविधा प्राप्त हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के इस बढ़ते उपयोग ने न केवल आम आदमी पर बिजली के बिल का बोझ कम किया है बल्कि बिजली उत्पादन की लागत में कमी लाते हुए प्रदेश सरकार के संकल्पों को भी मजबूती प्रदान की है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने का यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके साथ ही सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और गरिमामय अंतिम संस्कार व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित दर्जनों आधुनिक अन्त्येष्टि स्थलों ने ग्रामीण जनता को एक बड़ी सुविधा प्रदान की है। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित जन सेवा केंद्रों ने नागरिक सेवाओं को सीधे ग्रामीणों के द्वार तक पहुँचा दिया है। विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र, आवेदन और योजनाओं की जानकारी अब स्थानीय स्तर पर ही सुलभ है जिससे ग्रामीणों के समय और धन दोनों की बड़ी बचत हो रही है। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था ने पंचायतों के कार्यों और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाते हुए भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया है और विकास की गति को तेज किया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी पंचायतों ने उल्लेखनीय कार्य किया है जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और स्वयं सहायता समूहों के साथ उनके बेहतर समन्वय ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को अभूतपूर्व बल दिया है। जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए मनरेगा और अमृत सरोवर जैसी योजनाओं का प्रभावी उपयोग किया गया है। ऐतिहासिक तालाबों का पुनरुद्धार और व्यापक वृक्षारोपण जैसे कार्यों ने ग्रामीण पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित किया है जिससे भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्गों और पात्र लाभार्थियों को सीधे लाभान्वित किया है। जिला प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता से इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुँच रहा है जिससे उनके सामाजिक जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आया है। आज लखनऊ के ग्रामीण अंचल में जो व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह केवल आंकड़े नहीं है बल्कि बदलते हुए, जीवंत परिवेश की एक खूबसूरत तस्वीर है। डिजिटल पंचायत, आत्मनिर्भरता और आधुनिक बुनियादी ढांचे के इस बेहतरीन संगम ने भविष्य के ''स्मार्ट ग्राम'' की एक मजबूत नींव रख दी है।

एनटीए ही निकला माफिया

नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद एक के बाद एक छात्र-छात्राओं द्वारा मौत को गले लगाने के बाद मचे भारी बवाल और चौतरफा आलोचनाओं के बीच केन्द्र सरकार ने बड़े प्रशासनिक कदम उठाए हैं। परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए की साख पर लगे गम्भीर दाग धोने के लिए एनटीए के दो नए संयुक्त सचिव और दो नए संयुक्त निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। छात्रों की आत्महत्या को सिस्टम द्वारा की गई हत्या करार दिया जा रहा है जिससे जनाक्रोश भी दिखाई देता है। लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए यह पहला प्रशासनिक फेरबदल है। यद्यपि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा दोबारा 21 मई को कराने की तिथि घोषित कर दी है और अगले वर्ष परीक्षा ऑनलाइन कराने का भी ऐलान कर दिया है लेकिन लीक और गोपनीयता भंग ने राष्ट्रीय परीक्षा एजैंसी की विश्वसनीयता पूरी तरह से नष्ट कर दी है। पेपर लीक प्रकरण में एनटीए की साख खत्म होने का बड़ा कारण मास्टर माइंड दो प्रोफैसरों की गिरफ्तारी है जो एनटीए की परीक्षा पेपर बनाने वाली समिति से जुड़े हुए थे। इससे स्पष्ट है कि एनटीए के कुएं में भंग पड़ी हुई थी। माफिया खुद एनटीए से जुड़े लोग ही निकले। उनके तार संगठित गिरोह, धन के लोभी, संवेदनहीन साजिशकर्ताओं से जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक बार फिर युवा वर्ग को हताश किया और उनकी उम्मीदें छीन लीं। कहने को तो हम विश्व गुरु हैं। विशाल जनसंख्या वाले देश में हम सफलतापूर्वक जनगणना करा लेते हैं। चुनावों से पहले दिन-रात एक करके मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी करा लेते हैं। अंतरिक्ष में हमारी धाक है। हम चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बिना लीक के परीक्षा नहीं करवा सकते। स्पष्ट है कि सिस्टम में ही काली भेड़ें छिपी हुई हैं। लिहाजा मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार के लिए बनाई गई राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को भी पूरी तरह से लागू करने की बात कही है लेकिन सवाल यह भी है ?कि यह सिफारिशें पहले लागू क्यों नहीं की गईं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है लेकिन बार-बार पेपर लीक हो जाने के बाद भी पहले कोई कदम नहीं उठाए गए। जबकि कुछ अन्य परीक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं तो नीट परीक्षा के ऑनलाइन करने में विलम्ब क्यों हुआ। नीट परीक्षा शुरू से विवादों से घिरी रही है, कई राज्यों ने तो इस प्रारूप का ही विरोध किया लेकिन इसके बावजूद जब इसे देश भर में लागू कर दिया गया तो परीक्षा कराने वाली एजैंसी एनटीए को अपनी विश्वसनीयता पर गंभीर चोटें सहनी पड़ी हैं और विभिन्न किस्म के आरोप एवं विवाद निराशाजनक रूप से नियमित अंतराल पर सामने आते रहे हैं। इसमें तमिलनाडु में हुआ साल 2019 का घोटाला जिसमें छात्रों ने परीक्षा लिखने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया। केरल में साल 2022 का लड़की परीक्षार्थियों की जामा-तलाशी का विवाद और साल 2024 का पेपर लीक और ग्रेस मार्क विवाद शामिल हैं। पेपर लीक के सहारे राजस्थान में एक युवा नेता के परिवार के चार बच्चे डॉक्टर बन गए। इससे स्पष्ट है कि देश के डॉक्टर कितने प्रतिभाशाली होंगे डॉक्टरों को मरीजों के लिए भगवान स्वरूप माना जाता है। अगर वे लाखों में लीक वाले प्रश्नपत्र खरीद कर पास हुए हैं तो क्या इस वर्ग को छोड़ा जा सकता है। 23 लाख बच्चों के भविष्य पर जो आघात हुआ है वह असहनीय है। लाखों युवाओं में कई प्रतिभावान और विशेषज्ञ डॉक्टर बनने की योग्यता रखते होंगे जो लाखों की जिन्दगियां बचा सकते थे। हो सकता है अभिभावकों ने कर्ज लेकर बच्चों की तैयारी करवाई होगी लेकिन माफिया ने उनके सपनों को खंड-खंड कर दिया। सवाल यह भी है कि पेपर लीक माफिया और नकल माफिया पहले भी पकड़े जाते रहे हैं लेकिन आज तक उनको कितनी सजाएं हुईं। किस पर स्थायी पाबंदी लगाई गई। इसका कोई जवाब नहीं। बड़े-बड़े माफिया जमानत पर बाहर हैं और केस ठप्प हैं। छात्रों की आत्महत्याओं के बाद एक अत्यंत संवेदनशील पक्ष छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य और अभिभावकों की भूमिका का भी सामने आया है। देश में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि ऐसी परिस्थितियों में अभिभावक अपने बच्चों को डिप्रेशन से कैसे बचाएं। कहते हैं असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। परीक्षा रद्द होना या परीक्षा में असफल होना जीवन का अंत नहीं है। ऐसे समय में अभिभावकों को बच्चों पर बहुत अधिक दबाव बनाने की बजाय उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि बच्चे किसी भी तरह के आत्मघाती विचारों से दूर रह सकें। राधाकृष्णन कमेटी ने एनटीए के पुनर्गठन और एक सुरक्षित परीक्षा प्रशासन तंत्र निर्मित करने के लिए राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ एक मजबूत संस्थागत जुड़ाव बनाने की सिफारिश की। इनके अलावा, उसने बहु-चरणीय परीक्षा, कागज और कंप्यूटर के हाइब्रिड इस्तेमाल और सेंध व कदाचार रोकने के उपायों की श्रृंखला की भी सिफारिश की। एनटीए को लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित करने वाली, संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं का अपना अकुशल संचालन जारी रखने देना अपराध होगा। मेडिकल में दाखिले के लिए एकल, मानकीकृत और पारदर्शी प्रवेश परीक्षा लागू करने के उपाय के रूप में नीट को लाया गया था। बेहतर होगा मौजूदा एनटीए को बर्खास्त कर परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं।

सम्पादकीय...

आगे बढ़ रहा है लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत जनपद लखनऊ में निराश्रित और बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए एक अत्यंत सुव्यवस्थित ढांचा विकसित किया गया है। वर्तमान में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों की संख्या में आश्रय स्थल संचालित हैं, जो न केवल गोवंश को सुरक्षित आवास प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उनके आहार, पेयजल और स्वास्थ्य की भी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। इन प्रयासों के केंद्र में प्रदेश सरकार की वह संकल्पना है, जिसमें पशुधन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। जनपद में संचालित कान्हा उपवन जैसे विशाल केंद्रों ने निराश्रित, बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को नया जीवन प्रदान किया है। 53 बीघा जैसी विस्तृत भूमि पर स्थापित ये केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। जहाँ गोवंश की देखरेख के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों का ही परिणाम है कि आज लखनऊ में गोवंश सहभागिता योजना के माध्यम से आम नागरिकों और किसानों को सीधे इस पवित्र अभियान से जोड़ा गया है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को न केवल गोवंश सौंपे जाते हैं, बल्कि उनके भरण-पोषण के लिए मासिक आर्थिक अनुदान भी सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सामाजिक सहभागिता और आर्थिक सहयोग का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलावों ने जनपद के पशुधन की सुरक्षा को नया विस्तार दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और डिवर्मिंग जैसे अभियानों ने लंपी वायरस जैसे संक्रामक रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त की है। जिला प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक आश्रय स्थल पर पशुओं के लिए उचित उपचार कक्ष और गंभीर रूप से बीमार पशुओं के लिए पृथक वार्ड उपलब्ध हों। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संचालित मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स ने चिकित्सा सेवाओं को पशुपालकों के द्वार तक पहुँचा दिया है, जिससे समय पर इलाज मिलने से पशुहानि में भारी कमी आई है। पिछले नौ वर्षों के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो लखनऊ जनपद में लगभग 31,343 गोवंशों का संरक्षण 101 गो आश्रय स्थलों में किया गया है, जो पशु कल्याण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु 16.11 करोड़ रुपये की लागत से 14 वृहद गो संरक्षण केंद्रों का निर्माण कराया गया है, जो गोवंश संरक्षण के लिए एक स्थायी और दीर्घकालिक आधारभूत संरचना के रूप में उभरे हैं। प्रदेश सरकार की योजनाएं केवल उपचार और संरक्षण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये पशुपालकों की आय में वृद्धि और ग्रामीण समृद्धि का भी बड़ा आधार बनी हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मिनी नंदिनी जैसी पहलों ने लखनऊ के डेयरी क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। इन योजनाओं के माध्यम से स्थानीय लाभार्थियों को लाभान्वित कर स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मार्ग खोले गए हैं। इसी प्रकार नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन आधारित आजीविका, नस्ल सुधार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण नवाचार किए गए हैं। कुक्कुट विकास योजना ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का एक वैकल्पिक और सशक्त स्रोत प्रदान किया है।

यह हो क्या रहा है आसपास ?

अब अधिकांश लोग इन खबरों से दूरी बनाए रखने के लिए प्रयासशील रहते हैं। यदि कोई नेता पत्रकारों से सामीप्य बनाए रखता है तो वह भी अपने प्रचार के लिए नहीं बल्कि अपने विपक्ष के खिलाफ 'कवरेज' के लिए प्रयासशील रहता है। यह स्थिति पंजाब के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी है। एक ओर महाराणा प्रताप जयंती के विज्ञापन छपे हैं तो उसी पृष्ठ पर या सामने वाले पृष्ठ पर 'नीट-परीक्षाओं' में धांधलियों की खबरें चस्पा हैं। नज़र महानायकों की शौर्य गाथाओं पर कम और धांधलियों वाली खबरों पर ज्यादा टिकती है। स्थितियां तब और भी निराश करती हैं जब 'मां, मानुष और माटी' के झण्डे बुलंद करने वाली ममता दीदी अपने ही बुने जंजालों में फंस जाती है। उनकी रबर की चप्पल, सूती धोती व 'पेंटिंग्स' और कविताओं की पुस्तकें, सब हाशिए पर सरकने लगते हैं। यानी बकौल दुष्यंत, 'आप बच कर चल सकें,ऐसी कोई सूरत नहीं'। उधर बंगाल में एक बार फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने की मांग को लेकर दंगे भड़काने का प्रयास हो रहा है। ऐसे माहौल में प्रार्थना करें संवाद और स्नेह की बयार बहे ताकि यह उबलता हुआ परिवेश शांत हो जाए। युवाओं में तनाव मुक्ति के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) की ओर से कॉलेजों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया। इसमें शिक्षकों और प्रशासन को छात्र मानसिक तनाव पहचानने और संकट प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू किया गया है। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एंटी-रैगिंग समितियां और स्क्वायड अनिवार्य किए गए रैकिंग विद्यार्थी के आत्महत्या का एक प्रमुख कारण माना जाता है। 24म7 एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन (1800-180-5522) और शिकायत पोर्टल को सभी संस्थानों में लागू किया गया। शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण शुरू किया गया ताकि वे विद्यार्थियों के व्यवहार, तनाव और भावनात्मक बदलाव को पहचान सकें।

आसपास हताशा के कितने काले सियाह बादल उमड़ने लगे हैं। 'नीट' की परीक्षाओं में घोटाला 'पंजाब बिजिलेंस के मुख्यालय पर सीबीआई का छापा, सर्वोच्च न्यायालय में चंडीगढ़-प्रशासन की सार्वजनिक खिंचाई, पंजाब के मंत्री की गिरफ्तारी, कहीं भी तो उम्मीद की कोई किरण नहीं फूट रही।' 'आत्महत्या' की ओर बढ़ने वालों में युवा भी हैं, विद्यार्थी भी, किसान भी, महिलाएं भी और उच्च पदस्थ अधिकारी भी। इनमें सबसे बड़ा कारण है संवाद का अभाव। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। सबने संवाद की खिड़कियां बंद कर रखी हैं। यदि आप कविता-माध्यम से इस बात का मर्म समझ सकते हैं तो राही मासूम रज़ा साहब की नज़्म पढ़ लें-

'ये दुनिया तन्हा लोगों की।
इक महफिल है।
कृष्ण अकेला, मधुबन तन्हा।
गाय अकेली, माखन तन्हा।
हाथ अकेले, दामन तन्हा।
नींद अकेली-आंगन तन्हा।
कोई किसी का दर्द न जाने।
कोई किसी की बात न माने।

हरियाणा की गणना इन दिनों देश के सर्वाधिक विकासशील राज्यों में हो रही है। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में हरियाणा में 3360 लोगों ने जिंदगी की विषमताओं से हताश होकर आत्महत्या कर ली। जाहिर है कि औसतन 9 हरियाणवी लोग प्रतिदिन मौत को गले लगाते हैं और गत वर्ष 2025 व 2026 के प्रथम चार महीनों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले दिनों तो सचिवालय की ऊपरी मंजिलों से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की खबरें भी चर्चा में रहीं। यह तथ्य भी कम चौंकाने वाला नहीं है कि हेल्पलाइन 14416 पर हर रोज़ औसतन एक कॉल आत्महत्या करने वालों की भी आती है मगर जब तक पुलिस पहुंच पाती है, घटना घट चुकी होती है। यह हेल्पलाइन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसिक रोगों की रोकथाम एवं परामर्श के लिए आरंभ की गई थी। आत्महत्या पर उतारू मानसिकता को समझने के लिए साहित्यकार साहिर लुधियानवी की एक नज़्म की चार पंक्तियां भी दिमाग में कौंधती हैं। इस नज़्म को विस्तार से 'इंटरनेट' पर भी पढ़ा जा सकता है। शुरुआत इस तरह से है -शीर्षक है 'खुदकुशी से पहले'

उफ़ ये नौखेज़ सियाही, ये हवा के नौहे।
किसको मालूम है,
इस शब की सहर हो के न हो।

डराने वाले तथ्य सिर्फ हरियाणा से ही नहीं जुड़े, पड़ोसी पंजाब में स्थिति इससे भी बुरी है। वहां अधिकांश घरों में 'चिट्टे' की शोक कथाएं 'सोग' (शोक) का माहौल बन रही है। यह महान गुरुओं, संतों व पीरों की धरती है, मगर हर व्यक्ति दूसरे से डरा हुआ है। कीचड़ इतना कि इसे बुहारने में भी सब डरते हैं कि छींटे अपने ही दामन पर न पड़ जाएं। अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी जांच-पड़तालों के घेरे में हैं। नेतागण सहमे हुए हैं, कब कोई पिटारा खुल जाए। ऐसा भी नहीं कि पूरा परिवेश बेईमान है। मगर भय इतना गहरा गया है कि अधिकारी लोग न्यायोचित बातों या कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुए डरते हैं। पिछले दिनों एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मिले।

उन्हें कुछ समय पूर्व महत्वपूर्ण नियुक्तियों से दूर कर दिया गया। मगर उक्त अधिकारी संतुष्ट है। उसे उपेक्षा पसंद है। उसका तर्क है कि मुख्यधारा में बने रहेंगे तो न जाने क्या-क्या झेलना पड़े। पहले 'मीडिया-हाइप' के लिए अधिकारीगण, नेतागण और बुद्धिजीवी दीवाने हो जाते थे। अब अधिकांश लोग इन खबरों से दूरी बनाए रखने के लिए प्रयासशील रहते हैं। यदि कोई नेता पत्रकारों से सामीप्य बनाए रखता है तो वह भी अपने प्रचार के लिए नहीं बल्कि अपने विपक्ष के खिलाफ 'कवरेज' के लिए प्रयासशील रहता है। यह स्थिति पंजाब के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी है। एक ओर महाराणा प्रताप जयंती के विज्ञापन छपे हैं तो उसी पृष्ठ पर या सामने वाले पृष्ठ पर 'नीट-परीक्षाओं' में धांधलियों की खबरें चस्पा हैं। नज़र महानायकों की शौर्य गाथाओं पर कम और धांधलियों वाली खबरों पर ज्यादा टिकती हैं। स्थितियां तब और भी निराश करती हैं जब 'मां, मानुष और माटी' के झण्डे बुलंद करने वाली ममता दीदी अपने ही बुने जंजालों में फंस जाती है। उनकी रबर की चप्पल, सूती धोती व 'पेंटिंग्स' और कविताओं की पुस्तकें, सब हाशिए पर सरकने लगते हैं। यानी बकौल दुष्यंत, 'आप बच कर चल सकें,ऐसी कोई सूरत नहीं'। उधर बंगाल में एक बार फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने की मांग को लेकर दंगे भड़काने का प्रयास हो रहा है। ऐसे माहौल में प्रार्थना करें संवाद और स्नेह की बयार बहे ताकि यह उबलता हुआ परिवेश शांत हो जाए। युवाओं में तनाव मुक्ति के लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) की ओर से कॉलेजों के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया। इसमें शिक्षकों और प्रशासन को छात्र मानसिक तनाव पहचानने और संकट प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू किया गया है। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एंटी-रैगिंग समितियां और स्क्वायड अनिवार्य किए गए रैकिंग विद्यार्थी के आत्महत्या का एक प्रमुख कारण माना जाता है। 24म7 एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन (1800-180-5522) और शिकायत पोर्टल को सभी संस्थानों में लागू किया गया। शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण शुरू किया गया ताकि वे विद्यार्थियों के व्यवहार, तनाव और भावनात्मक बदलाव को पहचान सकें। सरकारी व निजी स्कूलों में अनिवार्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही विद्यार्थियों के व्यवहार को पहचानने के लिए शिक्षकों को संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूलों में एंटी-रैगिंग समितियां सक्रिय की गई हैं। इसी तरह अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों में माता-पिता को शामिल किया जा रहा है। स्कूल परिसरों में नियमित सुरक्षा निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है।

चुनौतियों से समाधान तक, आत्मनिर्भरता की ओर एक ठोस कदम

सेमीकंडक्टर उद्योग, जो उच्च मूल्यवर्धन और निर्यात क्षमता वाला क्षेत्र है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख साधन बन रहा है । उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर यह नीति मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को सुदृढ़ कर रही है। देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलने से आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 राज्य की औद्योगिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण ठोस कदम है।

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 का उद्देश्य प्रदेश को पूरे देश में सेमीकण्डक्टर निर्माण के क्षेत्र में प्रमुख हब के रूप में स्थापित करना है। भारत को सेमीकण्डक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करते हुए तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। आज के डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर केवल एक तकनीकी उत्पाद नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन चुके हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य उपकरण और रक्षा प्रणाली हर क्षेत्र सेमीकण्डक्टर पर निर्भर है। इसके बावजूद, लंबे समय तक भारत सेमीकंडक्टर के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न वैश्विक चिप संकट ने इस निर्भरता की कमजोरियों को उजागर किया था। ऑटोमोबाइल उत्पादन ठप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग प्रभावित हुआ और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जनसंख्या बहुल राज्य के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण थी, जहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना और औद्योगिक विकास को गति देना एक निरंतर आवश्यकता है। तकनीकी क्षेत्र में सीमित निवेश, उच्च-स्तरीय अनुसंधान संस्थानों की कमी, और वैश्विक कंपनियों के लिए अनुकूल इकोसिस्टम का अभाव सभी बाधाएँ राज्य को इस उभरते क्षेत्र में पीछे रखती थीं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 को बनाकर लागू किया। यह नीति केवल एक औद्योगिक दस्तावेज नहीं, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए एक समग्र रणनीति के रूप में तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। सेमीकण्डक्टर विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने हेतु भारत सरकार की पहल के अनुरूप सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह एक स्वतन्त्र सेमीकण्डक्टर नीति प्रख्यापित की गई है। सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान आरम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है। नीति प्रख्यापन के प्रथम वर्ष में ही मैसर्स टॉर्क सेमीकण्डक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की रु 28,440 करोड़ तथा मैसर्स वामासुन्दरी इन्वेस्टमेण्ट्स (दिल्ली) प्रा0लि0 की रु 3,706.12 करोड़ के निवेश वाली दो वृहद परियोजनाओं को निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान कर लेटर ऑफकम्फर्ट निर्गत कर दिया गया है। लगभग रु0 506 करोड़ के निवेश वाला एक अन्य परियोजना-प्रस्ताव भी अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है। प्रदेश में निवेशकों के सामने उच्च लागत और जटिल प्रक्रियाओं को दूर करने एवं उनके समाधान के रूप में प्रदेश सरकार के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने पूंजीगत सब्सिडी, भूमि पर रियायत, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और बिजली दरों में राहत जैसी सुविधाएँ प्रदान की है। इसके साथ ही, एकीकृत सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे उद्योगों को स्वीकृति प्राप्त करने में कम समय लगे और अनावश्यक बाधाएँ समाप्त हों। उक्त बुनियादी ढाँचे के अभाव को दूर करने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग को अत्यधिक पूंजी गहन और तकनीकी अत्याधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता को दूर किया गया। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-6 क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया है। यह क्लस्टर वैश्विक कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है और इसके आसपास सहायक उद्योगों के विकास की भी संभावनाएँ पैदा करता है। कुशल मानव संसाधन की भी व्यवस्था की गई है। इस नीति के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सेंटर ऑफएक्सीलेंस की स्थापना की योजना के माध्यम से युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्राप्त कर रोजगार से लगें। उ0प्र0 सेमीकंडक्टर नीति आम नागरिकों के जीवन को भी सीधे प्रभावित करती है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता होती है।

उच्च-कुशल इंजीनियरों से लेकर तकनीशियनों और श्रमिकों तक विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर रोजगार मिलेगा और अन्य राज्यों या देशों की ओर पलायन में कमी आएगी। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर उद्योगों के विकास से छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। इस नीति में सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के सभी महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है। इसमें फैब्रिकेशन यूनिट्स (फ्ब) डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, ।ेेमउइसल ज्मेजपदह (ंदक च्ंबांहपदह). डिजाइन यूनिट्स और सप्लाई चेन से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल एक क्षेत्र में विकास करना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार करना है, जहाँ सभी गतिविधियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हों और सामूहिक रूप से विकास को गति दें। वर्तमान में इस नीति के तहत निवेश आकर्षित करने के प्रयास तेज हो चुके हैं। विभिन्न निवेश सम्मेलनों के माध्यम से राज्य सरकार वैश्विक कंपनियों के साथ संवाद स्थापित कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020, डेटा सेंटर नीति-2021 और स्टार्टअप नीति-2020 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक मजबूत डिजिटल और औद्योगिक आधार तैयार किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा क्षेत्र पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के हब के रूप में विकसित हो रहे हैं, और अब सेमीकंडक्टर नीति के माध्यम से इस विकास को नई दिशा मिल रही है। यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकार ने जो 01 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसके लिए उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना आवश्यक है। सेमीकंडक्टर उद्योग, जो उच्च मूल्यवर्धन और निर्यात क्षमता वाला क्षेत्र है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख साधन बन रहा है । उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर यह नीति मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को सुदृढ़ कर रही है। देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलने से आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 राज्य की औद्योगिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण ठोस कदम है। यह नीति न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार कर रही है। रोजगार सृजन, तकनीकी आत्मनिर्भरता, वैश्विक निवेश और आर्थिक विकास इन सभी पहलुओं को समाहित करते हुए यह नीति उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो रही है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीतमपुरा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/00882)

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को किया मुग्ध, धूमधाम से मनाया गया जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज का 33वां स्थापना दिवस

कप्तानगंज, कुशीनगर।

कप्तानगंज स्थित जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज का 33वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया गया। देर रात तक चले इस भव्य कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं क्षेत्रीय लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, खड्डा विधायक विवेकानंद पाण्डेय तथा हाटा विधायक मोहन वर्मा रहे। वहीं नगर पंचायत रामकोला के चेयरमैन प्रतिनिधि सतीश चौधरी, कप्तानगंज मंडल भाजपा अध्यक्ष हरेराम गुप्त सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद

विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत, कुल गीत, देशभक्ति गीत, राजस्थानी भावनृत्य, झांसी की रानी पर आधारित लघु नाटिका, शिव वंदना नृत्य सहित कई आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के पुरातन छात्रों द्वारा भी मनमोहक गीत प्रस्तुत किए गए। इसमें प्रमुख रूप से तेज सिंह कुशवाहा, मानसी सिंह, आयुषी सिंह, देवानंद, निशा भारती, मोनिका अग्रहरी सहित अन्य छात्र-छात्राएं शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान जादूगर करण रैना ने अपनी जादू कला एवं गोरिल्ला डांस से उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड्डा विधायक विवेकानंद पाण्डेय ने कहा कि शिक्षण संस्थान राष्ट्र की प्रगति के आधार होते हैं। राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब शिक्षक एवं विद्यार्थी पूरी निष्ठा और मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हाटा विधायक मोहन वर्मा ने शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए विद्यार्थियों को मेहनत एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने कहा कि जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज ने पिछले 33 वर्षों में अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीराम प्रसाद ने कहा कि विद्यालय के अनेक छात्र आज प्रशासनिक सेवा, न्यायपालिका, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, राजनीति, विज्ञान एवं कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश और समाज की सेवा कर रहे हैं तथा विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं।

इस अवसर पर विशम्भर प्रसाद, राधेश्याम दीक्षित, चन्दन कुमार गोंड, नीरज तिवारी, उदयभान सिंह, जयराज सिंह, राजेश मिश्रा, सतीश चौधरी, आर.के. भट्ट, सीमा कसौधन, ज्ञानवर्धन, गोविन्द राव, आफताब आलम, संजय प्रताप सिंह, मुकेश सिंह, सुरजीत गौड़, वशिष्ठ दुबे, सुरेश चंद, पी.एन. पाण्डेय, लाल बहादुर मल्ल, आजाद प्रसाद, डॉ. सदानंद कुशवाहा, गोलू मिश्रा, रघुपति सिंह, दिनेश यादव, के.के. यादव, शिव प्रताप सिंह, नीरज कुमार, हरिश्चंद्र सिंह, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीप्ति राय, रामदरस शर्मा, प्रेमनारायण पाण्डेय, अनुप सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

आनंदनगर,महराजगंज ।

रविवार को लखनऊ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन फरेंदा के अधिवक्ताओं ने तीन सूत्रीय मांगपत्र उपजिलाधिकारी फरेंदा शैलेंद गौतम को सौंपा।

अधिवक्ताओं ने प्रशासन के दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की उपस्थिति लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रेमकुमार सिंह व मंत्री अजीत मणि त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले थाना ठाकुरगंज के प्रभारी व दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लाठीचार्ज में घायल अधिवक्ताओं के समुचित इलाज की व्यवस्था व आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ बार बार हो रही घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सरकार द्वारा तत्काल अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष राम सहाय गुप्ता व अरविंद कुमार मिश्र, विनय श्रीवास्तव, सतेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र श्रीवास्तव, सुनील मणि त्रिपाठी,मोहई खा, सुरेन्द्र पाण्डेय,मनोज कुमार मिश्र, अरविन्द उपाध्याय, अतुल श्रीवास्तव अनिल मौर्य,ओंकार मौर्या, शशांक त्रिपाठी, मृदुल यादव,अनिमेष चौधरी, रत्नेश त्रिपाठी, गिरधारी जायसवाल, मोहम्मद उस्मान, तेज प्रताप सिंह, विजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

जनता दर्शन से सीधे ऑन-स्पॉट एक्शन- सलेमपुर के बंजरिया शुक्ल पहुंचे डीएम, विधवा महिला की जमीन को कराया कब्जा मुक्त

देवरिया।

उत्तर प्रदेश शासन के मंशानुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन की संवेदनशीलता सोमवार को उस वक्त धरातल पर नजर आई, जब जिलाधिकारी स्वयं एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाने उसके गांव पहुंच गए। आमतौर पर जनता दर्शन में मिलने वाले प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को अग्रेषित कर समय-सीमा तय कर दी जाती है, लेकिन जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने इस ढर्रे को बदलते हुए सीधे मौके पर जाकर हस्तक्षेप किया। तहसील सलेमपुर क्षेत्र के ग्राम बंजरिया शुक्ल में हुए इस त्वरित प्रशासनिक एक्शन ने न केवल एक बेसहारा महिला को उसका हक दिलाया, बल्कि भूमाफिया और अवैध कब्जाधारकों को भी कड़ा संदेश दिया है। प्रकरण सलेमपुर के ग्राम बंजरिया शुक्ल का है, जहां की

निवासी शोभा देवी पत्नी स्वर्गीय अजय निषाद ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन में जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित विधवा महिला ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि गांव के ही कुछ रसूखदार दबंगों द्वारा उसकी पैतृक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण वह दर-दर भटकने को मजबूर है। मामले की गंभीरता और महिला की लाचारी को देखते हुए जिलाधिकारी ने फाइलों को आगे बढ़ाने के बजाय सीधे मौके पर जाने का निर्णय लिया। वे तत्काल प्रशासनिक और राजस्व अमले के साथ सीधे बंजरिया शुक्ल गांव पहुंच गए। जिलाधिकारी के अचानक गांव पहुंचने से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया। डीएम ने तत्काल सलेमपुर तहसील की राजस्व टीम को मौके पर तलब किया और विवादित भूमि के अभिलेख खंगाले। उन्होंने दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाकर साक्ष्यों की पड़ताल कराई और पूरी पारदर्शिता के साथ मौके पर ही भूमि का सीमांकन

शिकायत मिलते ही अमले के साथ खुद पीड़ित महिला के द्वार पहुंचे जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी; राजस्व टीम को मौके पर बुलाकर पैमाइश के साथ कराया विवाद का पटाक्षेप; बोले— गरीबों और असहायों की जमीन हड़पने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई

कराकर विवाद का स्थाई निस्तारण सुनिश्चित कराया। जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को दो टूक हिदायत दी कि जनपद में राजस्व संबंधी शिकायतों को ठंडे बस्ते में न डाला जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबों, वंचितों और महिलाओं की जमीनों पर अवैध कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ कठोरतम विधिक रुख अपनाया जाएगा।

अमजद खान ‘तमन्ना’ चौथी बार बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

दरबारे मौला एवं हजरत अलाउद्दीन शाह भटनी शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन को मिली नई जिम्मेदारी

भटनी देवरिया।

दरबारे मौला एवं हजरत अलाउद्दीन शाह भटनी शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमजद खान तमन्ना को आल इंडिया उलमा बोर्ड का लगातार चौथी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना नौशाद अहमद द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अल्लामा बनाई हसन की संस्तुति पर किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। बधाई देने वालों में निश्चल चौधरी एडवोकेट, आस मोहम्मद एडवोकेट, आशिष त्रिवेदी एडवोकेट, सलीम अहमद, रियाज बेग एडवोकेट, देवराज, आविद अली, सादाब सुहैल, डॉ शेखर सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे।

भटनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान

भटनी देवरिया। थाना जीआरपी भटनी द्वारा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भटनी रेलवे स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट हाल, यात्री प्रतीक्षालय, पार्किंग क्षेत्र तथा सभी प्लेटफार्मों पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वस्तुओं की गहन जांच की गई। पुलिस टीम ने यात्रियों को सुरक्षा के प्रति सतर्क एवं सजग रहने के लिए जागरूक भी किया। जीआरपी थानाध्यक्ष अजय कुमार मौर्य मयफोर्स के साथ यात्रियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा लावारिस वस्तु दिखाई देने पर तत्काल रेलवे पुलिस को सूचना दें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कुरमौटा गांव में ट्रांसफार्मर में लगी आग, मचा हड़कंप

भीषण गर्मी में बार-बार ट्रांसफार्मर जलने से उपभोक्ता परेशान

भटनी देवरिया। कुरमौटा गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया तथा विद्युत विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी और अधिक लोड के कारण क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम

जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने से गांव की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई, जिससे लोगों को गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से जल्द ट्रांसफार्मर बदलने एवं बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।

विद्यालयों में आम वितरण को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह

जौनपुर । जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन. के निर्देशानुसार सोमवार को जनपद के कंपोजिट एवं प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को फल वितरण कार्यक्रम के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बच्चों के बीच आम वितरित किए और बच्चों के साथ समय बिताया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक सोमवार को विद्यालयों में बच्चों को फल वितरित किया जाता है। वर्तमान समय आम का सीजन होने के कारण बच्चों को पौष्टिक फल के रूप में आम उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास को मजबूती मिले। विद्यालयों में आम वितरण को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने खुशी-खुशी आम ग्रहण किया और विभाग की इस पहल की सराहना की। विद्यालय स्टाफ ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग दिया।

अप्रैल की बरसात भी कम न कर सकी प्रदूषण, दिल्ली में और मैली हुई यमुना; मल-मूत्र से फैली गंदगी

दिल्ली । तमाम दावों के बावजूद दिल्ली में यमुना स्वच्छ होने के बजाय और मैली हुई है। अप्रैल में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ। यह खुलासा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। 7 अप्रैल को लिए गए नमूनों में अधिकांश हिस्सों में पानी अत्यंत प्रदूषित पाया गया है। कई स्थानों पर जलीय जीवन के लिए स्थिति अनुकूल तक नहीं पाई गई है। हाल के वर्षों में दिल्ली में अप्रैल का महीना सबसे अधिक बारिश वाला रहा है, लेकिन इस ज्यादा बारिश से यमुना को साफ करने में ज्यादा मदद नहीं मिली है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि यमुना और मैली हुई है। 7 अप्रैल को लिए गए जल नमूनों के आधार पर जारी रिपोर्ट में नदी के अधिकांश हिस्सों में पानी अत्यंत प्रदूषित पाया गया है। कई स्थानों पर जलीय जीवन के लिए स्थिति अनुकूल तक नहीं पायी गई है। प्रत्येक माह यमुना की जल गुणवत्ता की रिपोर्ट डीपीसीसी जारी करता है। इसके लिए पल्ला, वजीराबाद, आईएसबीटी ब्रिज, आईटीओ ब्रिज, निजामुद्दीन ब्रिज, हिंडन कट, ओखला बैराज और असगरपुर आठ स्थानों से नदी के जल के नमूने लेकर जांच की जाती है। बीओडी, घुलित आक्सीजन (डीओ), रासायनिक आक्सीजन मांग (सीओडी), पीएच और फीकल कोलीफार्म जैसे मानकों की जांच कर प्रदूषण स्तर का आकलन किया जाता है। अप्रैल की रिपोर्ट में इनमें से पांच स्थानों पर फीकल कोलीफार्म के स्तर में मामूली सुधार दर्ज किया गया लेकिन सभी स्थानों पर यह स्तर निर्धारित सीमा से अधिक है। पानी में फीकल कोलीफार्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर अधिकतम 500 सर्वाधिक संभावित संख्या (एमपीएन) होना चाहिए। इसका स्तर 2,500 एमपीएन से अधिक होने पर पानी उपयोग योग्य नहीं रह जाता। रिपोर्ट के अनुसार, पल्ला और वजीराबाद क्षेत्रों को छोड़कर यमुना के लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर घुलित ऑक्सीजन (डीओ) का स्तर शून्य पाया गया है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में मछलियों और अन्य जलीय जीवों के जीवित रहने की संभावना नहीं है। वहीं, जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) भी मानकों से कई गुना अधिक दर्ज की गई है, जो अत्यधिक प्रदूषण की पुष्टि करता है। आईटीओ ब्रिज, आईएसबीटी ब्रिज, निजामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैराज और अन्य डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बेहद अधिक पाई गई, जो सीधे तौर पर सीवेज के बिना उपचारित पानी के नदी में मिलने को दर्शाता है। कुछ स्थानों पर यह स्तर लाखों एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर तक पहुंच गया, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली के कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई स्थानों पर फॉस्फेट और अमोनियाकल नाइट्रोजन की मात्रा भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। राजधानी के सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना नदी की सफाई के लिए रविवार को स्वस्ति दास सेवा संस्थान ने विशेष अभियान चलाया।

रूसी तेल खरीद पर अमेरिका ने फिर दी बड़ी राहत, प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट

वॉशिंगटन। अमेरिकी वित्त विभाग ने सोमवार को रूसी तेल की खरीद पर अस्थायी तौर से 30 की राहत दी है। अमेरिका के इस फैसले से कई देशों को फिलहाल समुद्र में फंसे रूसी तेल तक पहुंचने की सुविधा मिलने की संभावना है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने और ऊर्जा-असुरक्षित देशों तक तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूसी तेल की खरीद पर यह विस्तार अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करेगा। विभाग देशों के साथ आवश्यकतानुसार विशिष्ट लाइसेंस प्रदान करने के लिए काम करेगा। इस सामान्य लाइसेंस का उद्देश्य कच्चे तेल के बाजार को स्थिर करना और यह सुनिश्चित करना है कि तेल सबसे ज्यादा ऊर्जा संकट से जूझ रहे देशों तक पहुंचे। इसके अतिरिक्त यह छूट चीन की रियायती तेल के भंडारण की क्षमता को कम करके, जरूरतमंद देशों तक मौजूदा आपूर्ति को फिर से रूट करने में भी मदद करेगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पहले जारी की गई 30-दिवसीय छूट की अवधि समाप्त हो गई थी। रूस के समुद्र में फंसे तेल के लिए पिछली 30-दिवसीय छूट 16 मई को समाप्त हो गई थी। मूल रूप से मार्च में दी गई यह अस्थायी छूट, सक्रिय प्रतिबंधों के बावजूद पारगमन में फंसे कार्गो को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचने की अनुमति देकर वैश्विक ईंधन आपूर्ति को सहारा देने के लिए दी गई थी। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से यह तीसरा ऐसा विस्तार है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था। वहीं, भारत ने स्पष्ट किया है कि तेल खरीद के संबंध में नई दिल्ली के फैसले उसके लोगों के हितों और व्यावसायिक समझ से निर्देशित होते हैं।

दिल्ली एनसीआर में अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ही चलेगा एग्रीगेटर कारोबार, हरियाणा कैबिनेट का अहम फैसला

***एनसीआर में 2026 से केवल सीएनजी-इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे**
***ऐप-आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को लाइसेंस लेना होगा**
***हिसार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भूमि पर शुल्क माफ**

■ गौर रहे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत करनाल तक के इलाके दिल्ली एनसीआर में आते हैं। प्रदेश के कुल 14 जिले एनसीआर में आंशिक और पूरी तरह आते हैं।

चंडीगढ़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण और ट्रैफिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं पर बड़ा फैसला लिया है। पहली जनवरी 2026 से एनसीआर क्षेत्र में एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाता और ई-कामर्स कंपनियां अपने बेड़े में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), बैटरी आपरेटेड व्हीकल (बीओवी) या अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित वाहन ही शामिल कर सकेंगी। नए आटो रिक्शा भी केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक ही होंगे। कैबिनेट ने सोमवार को हरियाणा मोटर व्हीकल रूल्स-1993 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और हरियाणा में 'क्लीन मोबिलिटी माडल' को तेजी से लागू करना है। एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। ड्राइवर आनबोर्डिंग, वाहन सत्यापन, साइबर सुरक्षा, किराया निर्धारण और शिकायत निवारण से जुड़े सख्त नियम लागू होंगे। एग्रीगेटर कंपनियों को यात्रियों के लिए कम से कम पांच लाख रुपये का बीमा कवर देना होगा।

कंपनियों को 24 घंटे और सातों दिन मिलेगी सर्विस

इसके अलावा ड्राइवरों के लिए पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और दस लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है।नई नीति के तहत वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी), पैनिक बटन, फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर लगाना जरूरी होगा। कंपनियों को 24×7 कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर स्थापित करने होंगे, ताकि यात्रियों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। ड्राइवर और वाहनों का सत्यापन 'वाहन' और 'सारथी' पोर्टल के जरिए किया जाएगा। कंपनियों को आनबोर्ड किए गए सभी ड्राइवरों और वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। नई नीति में दिव्यांगजन अनुकूल वाहनों को शामिल करने और चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ने का भी प्रावधान रखा गया है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आनलाइन पोर्टल के जरिए होगी, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कारिडोर परियोजना के तहत हिसार एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कारिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में 2988 एकड़ भूमि के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क माफ किया जाएगा। स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में करीब 132 करोड़ 51 लाख रुपये माफ किए जाएंगे। इसमें 132 करोड़ रुपये स्टांप शुल्क तथा 50 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क शामिल है।

मोदी सरकार में दूरदर्शिता की कमी- कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा- चुनाव तक सरकार ने सबकुछ छिपाकर रखा

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में दूरदृष्टि की कमी है और उन्होंने विधानसभा चुनावों तक देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को जनता से छिपाकर रखा गया। खरगे की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सरकार ने रविवार को सीएनजी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की। पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी बार है जब सीएनजी महंगी हुई है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर खरगे ने साधा निशाना

इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। ईरान युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से सरकारी तेल कंपनियों पर भारी दबाव पड़ रहा था। खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा पोस्ट में कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीजों के दाम बढ़ाते, तो उन्हें भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता।

खरगे ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आरोप लगाया, मोदी सरकार ने चुनाव खत्म होने तक देश से सब कुछ छिपाकर रखा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भाजपा सरकार और मोदी में दूरदृष्टि की कमी है, इसलिए उन्हें पहले से बढ़ती महंगाई का अंदाजा नहीं था।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी क्योंकि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। खरगे ने कहा, देश के गरीब लोग अपनी जरूरत की जरूरी चीजें तक नहीं खरीद पा रहे हैं।

फिर शुरू होगी जंग! यूएस ने ईरान का शांति प्रस्ताव ठुकराया, रिपोर्ट में दावा

रिपोर्ट-ईरान जंग के बीच 8000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी में तैनात जेएफ-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन स्क्वाड्रन भी भेजे, खर्च सऊदी सरकार उठाएगी

इंटरनेशनल डेस्क । अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी तनाव अब महायुद्ध की दहलीज पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताजा शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब कूटनीति के लिए समय बहुत कम बचा है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अपना रुख नहीं बदला, तो वाशिंगटन बमों के जरिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो सकता है।

पाकिस्तान के जरिए भेजा गया प्रस्ताव नाकाफी

सूत्रों के अनुसार, ईरान ने रविवार रात पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से एक संशोधित शांति प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था।

हालांकि, व्हाइट हाउस ने इसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि इसमें कोई सार्थक प्रगति नहीं है और यह अमेरिका की मुख्य चिंताओं को दूर करने में विफल रहा है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरानी मसौदे में परमाणु हथियार न बनाने की बात तो दोहराई गई है,

लेकिन यूरेनियम संवर्धन रोकने या समृद्ध यूरेनियम के भंडार को सौंपने पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई गई है।

घड़ी टिक-टिक कर रही है

राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा, घड़ी टिक-टिक कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तेहरान ने लचीलापन नहीं दिखाया, तो उसे बहुत बुरी तरह से निशाना बनाया जाएगा। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने दोटूक शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि ईरानी कुछ ठोस कदम उठाएं, वरना बमों के जरिए बातचीत होगी, जो कि एक शर्मनाक स्थिति होगी।

हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में ईरान की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाएगा और सैन्य विकल्पों सहित वैकल्पिक उपायों पर गहन चर्चा की जाएगी। अमेरिकी प्रशासन अब इस बात पर विचार कर रहा है कि बातचीत को और कितना आगे ले जाया जाए और कब कड़े कदम उठाए जाएं।

महाराष्ट्र के पालघर में कंटेनर और ट्रक की टक्कर में 13 बारातियों की मौत, 25 गंभीर रूप से घायल

मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर जिले से सोमवार तड़के एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई। मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कासा क्षेत्र के पास बारातियों से भरे एक ट्रक और तेज रफ्तार कंटेनर के बीच हुई भीषण टक्कर में 1 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं।

पुलिस के प्रारंभिक निरीक्षण और चश्मदीदों के बयानों के अनुसार, दुर्घटना का मुख्य कारण कंटेनर चालक की तेज रफ्तार और घोर लापरवाही रही। सोमवार तड़के करीब चार बजे, जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंधेरा और हल्का कोहरा था, गुजरात की ओर जा रहे एक विशाल कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण

खो दिया और सामने से आ रहे छोटे आईशर ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी।

बारातियों से भरा ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त

टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहन पलट गए और बारातियों से भरा ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक में सवार लोग डहाणू तहसील के बापूगांव से एक शादी समारोह में जा रहे थे। इस छोटे ट्रक में 40 से अधिक लोग सवार थे। पुलिस आशंका जता रही है कि सुबह के वक्त कंटेनर ड्राइवर को नींद की झपकी आई होगी। हादसे के बाद राजमार्ग पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद कासा पुलिस और हाईवे रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची।

क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर घायलों को निकाला

क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सीधा कर नीचे दबे यात्रियों को बाहर निकाला गया। 25 गंभीर घायलों को तुरंत पास के कासा उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां छह लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से गंभीर रूप से घायल चार लोगों को मुंबई और ठाणे के अस्पतालों में भेजा गया है। इस भीषण दुर्घटना के कारण मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और क्रेन से मलबे को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कंटेनर चालक दुर्घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए पांच-पांच लाख रुपयों की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है, तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। घायलों का इलाज निशुल्क करने के निर्देश भी दिए गए है।

नीट केस में महाराष्ट्र की केमिस्ट्री कोचिंग का डायरेक्टर अरेस्ट

■ सीबीआई को फोन में लीक पेपर मिला, सेंटर पर भी छापेमारी; अब तक 10 गिरफ्तार

मुंबई । नीट पेपर लीक केस में सोमवार को 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, रविवार को सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। सीबीआई के मुताबिक मोटेगांवकर संगठित गिरोह का हिस्सा है, जो नीट पेपर लीक कराने और आगे फैलाने में शामिल है। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल को ही पेपर और आंसर को हासिल की और कई लोगों को दी थी। सीबीआई ने 15 मई को मोटेगांवकर से उसके घर पर 8 घंटे पूछताछ की थी।

मोटेगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस नाम का कोचिंग सेंटर है। रविवार को सीबीआई ने आरसीसी के मेन ऑफिस पर छापा मारकर कई डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ का टर्नओवर है। सीबीआई को शक है कि सेंटर में नीट कैंडिडेट्स को लीक पेपर के सवाल उपलब्ध कराए गए। साथ ही लातूर के कई डॉक्टरों ने लीक पेपर खरीदा। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 6 महाराष्ट्र से हैं।

शुभेंदु का ऐलान- ममता सरकार के भ्रष्टाचार की कराएंगे जांच

महिला उत्पीड़न मामलों की हाईकोर्ट जज की अगुआई में जांच होगी; मौलवी-पुजारियों का मानदेय बंद

कोलकाता ।पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों और महिला उत्पीड़न की जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 2 आयोग बनेंगे। दोनों आयोगों की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। सरकार ने इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को 1 जून से बंद करने का फैसला किया है। साथ ही महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए देने, मुफ्त बस यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। बंगाल सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। सातवां वेतन

आयोग गठित करने और ओबीसी सूची में बदलाव जैसे अहम निर्णय भी लिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने मार्च में विधानसभा चुनावों के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को मिलने वाला मानदेय 500 बढ़ाया था। इसके बाद राज्य की रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को हर महीने 3000 रुपए, जबकि मुअज्जिन और पुजारियों को 2000 रुपए की मदद दी जा रही थी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि छात्रों को कोई भी छात्रवृत्ति योजना बंद नहीं की जाएगी।

गौतम अदाणी के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने हटाए सभी आरोप, मामला स्थायी रूप से किया बंद

न्यूयॉर्क । अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से हटा दिया है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में चल रहा बहुचर्चित रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों का मामला पूरी तरह से बंद हो गया है। इस फैसले के बाद अदाणी समूह से जुड़ी कई अमेरिकी नियामक और कानूनी जांचें बंद हो गई हैं। पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों को किए गए खुलासों से जुड़े गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ आरोपों का निपटारा किया। अदालत में दायर दस्तावेजों से पता चला कि गौतम अदाणी ने 60 लाख

अमेरिकी डॉलर और सागर अदाणी ने 120 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई, बिना किसी भी तरह की गलती स्वीकार किए या इनकार किए।

अब दोबारा नहीं खोला जा सकेगा मामला

विभाग ने कहा, न्याय विभाग ने इस मामले की समीक्षा की है और अपने अभियोजन विवेक के आधार पर, व्यक्तिगत प्रतिवादियों के खिलाफ इन आपराधिक आरोपों पर और अधिक संसाधन खर्च नहीं करने का फैसला किया है। न्याय विभाग ने अदालत में एक याचिका दायर कर अदाणी के खिलाफ आरोप-पत्र को विद प्रेजुडिस (स्थायी रूप से) खारिज करने का अनुरोध किया था। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपों को खारिज करने का आदेश दिया। विद प्रेजुडिस के साथ खारिज होने का मतलब है कि मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता। अमेरिकी आपराधिक कार्यवाही में ऐसे खारिज होना असामान्य है और यह आमतौर पर एक व्यापक समीक्षा के बाद यह निर्धारित करने को दर्शाता है कि मामले को आगे बढ़ाना अब उचित नहीं है। 2024 के आखिरी में दायर एसईसी और डीओजे के मामलों में आरोप लगाया गया था कि अदाणी ने सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को शामिल करते हुए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर रिश्वत दी थी। इसके साथ ही पूंजी जुटाते समय अमेरिकी निवेशकों और ऋणदाताओं से इसे छिपाया था। सूत्रों के अनुसार, अभियोजकों को स्पष्ट अमेरिकी संबंध नहीं मिले और आरोपों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त सबूत पाए गए, जिसके बाद मामला अदाणी के पक्ष में मुड़ गया। पांच अमेरिकी कानूनी सलाहकारों की एक टीम ने मामले की समीक्षा की। हालांकि, इस समीक्षा में गौतम और सागर अदाणी के खिलाफ आरोपों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त निष्कर्ष नहीं निकले, जिससे न्याय विभाग ने आरोपों को खारिज करने की ओर कदम बढ़ाया।

टीचर- इंजीनियर समेत 10 की मौत

लखीमपुर-खीरी ।लखीमपुर खीरी में सोमवार सुबह 7.30 बजे मैजिक वाहन और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मैजिक वाहन में सवार थे। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में सरकारी टीचर और इंजीनियर भी शामिल हैं। हादसा जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर पीलीभीत-बस्ती हाईवे पर अदलीसपुर गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मैजिक वाहन लखीमपुर से सिसैया की तरफ से जा रहा था। इसे बहराइच से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक में बैठे लोगों के सिर फट गए। लोग सीट के बीच में ही फंस गए। दो लोग उछलकर बाहर रोड पर गिरे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।